



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग (I) — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1327)

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 19, 2008/माद्रा 28, 1930

No. 1327)

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 19, 2008/BHADRA 28, 1930

अम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2008

का.आ. 2240(3)।—केन्द्रीय सरकार संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) को धारा 2 के खण्ड (d) के उप-खण्ड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के अम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14-3-2008 द्वारा कर्तृती नोट प्रेस, नासिक रोड, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 25 में शामिल है, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 21-3-2008 से छ: मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और, केन्द्रीय सरकार की रुप है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छ: मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (d) के उप-खण्ड (vi) के परन्तु कदाच प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 21-9-2008 से छ: मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/2/2006-आईआर (पी.एल.)]

एस. कृष्णन, विशेष सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2008

S.O. 2240(E).—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires that in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour dated 14-3-2008 the service in Currency Note Press, Nashik Road which is covered by item 25 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) to be a Public Utility Service for the purpose of the said Act, for a period of six months with effect from 21-3-2008.

And, whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares the said industry to be a Public Utility Service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 21st September, 2008.

[F. No. S-11017/2/2006-IR (PL)]

S. KRISHNAN, Sp. Secy.